डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 मार्च, 2021, डिस्पेच दिनांक 1 मार्च, 2021

| वर्ष 64 | अंक 19 | भोपाल | 1 मार्च, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

ई-उपार्जन पोर्टल पर 21.06 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

सहकारिता मंत्री श्री भदौरिया एवं खाद्य मंत्री श्री सिंह ने की उपार्जन पंजीयन की समीक्षा

भोपाल। रबी विपणन वर्ष 2021–22 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिये 21 लाख 6 हजार किसानों ने ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया है जो कि विगत वर्ष की तुलना में एक लाख 59 हजार अधिक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह और सहकारिता मंत्री श्री अरविन्द भदौरिया अधिकारियों के साथ रबी उपज की समीक्षा की।

145 लाख मे.टन उपज के भंडारण का लक्ष्य

मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि इस वर्ष 125 लाख मेट्रिक टन गेहूँ, 20 लाख मेट्रिक टन दलहन और तिलहन के भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपार्जन अनुमान के अनुसार अधिकारियों को अनाज के भंडारण, परिवहन, बारदाना और वित्तीय व्यवस्था की तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि दलहन एवं तिलहन का उपार्जन प्राथमिकता से गोदाम स्तरीय केन्द्रों पर किया जाएगा, जिससे स्कन्ध का शीघ्रता से परिवहन एवं भंडारण कराया जा सके।

15 मई तक होगा उपार्जन

सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि पंजीकृत किसानों से 15 मई तक उपार्जन पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वर्षा के पूर्व ही उपार्जित स्कन्ध को शीघ्रता से परिवहन किया जाकर भंडारण कराया जा सके। इससे वर्षा से होने वाली क्षति से बचा जा सकेगा। किसानों की सुविधा के लिये विगत वर्ष के अनुसार ही लगभग 4500 केन्द्रों पर गेहूँ का उपार्जन किया जाएगा।

प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि किसान पंजीयन का कार्य प्रदेश के 3518 केन्द्रों पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गिरदावरी किसान एप, कॉमन सर्विस सेन्टर, कियोस्क पर भी किसानों को पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विगत वर्ष 45 लाख 7 हजार हेक्टेयर रकबा गेहूँ के लिए पंजीकृत हुआ था। इस वर्ष अभी तक 42 लाख 87 हजार हेक्टेयर रकबा पंजीकृत हो चुका है। सभी किसानों का पंजीयन हो सके इसके लिए पंजीयन की तिथि 25 फरवरी तक की बढ़ाई गई है।

बैठक में मंत्रीद्वय के अलावा प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री पी. नरहरि, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री अभिजीत अग्रवाल, संचालक खाद्य एवं प्रबंध संचालक वेयर हाऊससिंग लाजिस्टिक कापार्रेशन श्री तरूण पिथोड़े एवं सहकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

एक छत के नीचे एक हजार युवाओं को मिल रहा निःशुल्क प्रशिक्षण

मंत्री श्री भार्गव की अभिनव पहल

भोपाल। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव की पहल पर सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के एक हजार से अधिक युवाओं को प्रतियोगी परिक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि रहली–गढ़ाकोटा क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिये सागर, भोपाल, इंदौर जाना होता है, जो काफी महंगा पड़ता है। स्थानीय लोगों की मांग पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए कोटिल्य अकादमी के विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा निशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। पुलिस विभाग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शारीरिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। स्विमिंग पूल में तैराकी का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि इसके अलावा सर्व सुविधा युक्त साढ़े सात सौ सीटर की क्षमता बाला ऑडिटोरियम बनाया गया है। ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक शैक्षणिक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसमें युवाओं के लिये जिम भी है, जिसमें एक्सपर्ट फिटनेस के लिए युवाओं को टिप्स देते हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्री श्री भार्गव द्वारा गढ़ाकोटा में गोपाल जी परिसर आउटडोर स्टेडियम भी तैयार कराया गया है, जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। आउटडोर स्टेडियम में पुलिस की तैयारी कर रहे युवक–युवतियों के लिए भी विशेषज्ञ द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है।

एक अप्रैल से होगा बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जानकारी दी है कि एक अप्रैल से कंपनी अपने केश काउण्टर बंद करने जा रही है। इसके विकल्प के तौर पर वर्तमान में चल रहे एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेन्टर, एटीपी मशीन, कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, ईबीपीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड, वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि) एवं उपाय मोबाइल एप विकल्पों द्वारा बिल भुगतान की सुविधा उपभोक्ताओं को उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा चिन्हित स्थानों पर चयनित एजेंसियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिकृत किया जाएगा।

दुग्ध संघ प्रतिनिधि मंडल के समस्याओं का निराकरण करायेंगे : मंत्री श्री सिलावट

कमलिया खेड़ी में दुग्ध उत्पादक किसानों को किया बोनस वितरण

भोपाल। लॉकडाउन के समय सांवेर क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों द्वारा अतिरिक्त दूध की मात्रा का सदुपयोग एवं नवाचार करते हुए दूध पाउडर बनाया गया। जल–संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने दुग्ध उत्पादक किसानों के नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म–निर्भर भारत अभियान के सपने को सच्चे अर्थों में सार्थक कर रहे हैं। उन्होंने सही मायनों में श्री मोदी के मंत्र ष्आपदा में अवसरश्श को बदलने को साकार करके दिखा दिया है। श्री सिलावट ने इंदौर में सांवेर ब्लॉक के ग्राम कमलिया खेड़ी में इंदौर दुग्ध संघ द्वारा 188 दुग्ध उत्पादक किसानों को 10 लाख 50 हजार रुपये का बोनस वितरित किया।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि दुग्ध उत्पादक संघ की समस्याओं का निराकरण प्रदेश–स्तर पर कराये जाने के लिये वे समुचित प्रयास करेंगे। उन्होंने दुग्ध उत्पादक संघ के प्रतिनिधि–मण्डल को भोपाल आने का आग्रह करते हुए कहा कि वे उनके साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट कर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री मोती सिंह पटेल ने आग्रह किया कि दुग्ध संघ में क़रीब पौने दो लाख लीटर दूध बच जाता है, जिसका दूध पाउडर बनाया जाता है। यह दूध पाउडर अगर सरकार ख़रीदे, तो इससे किसानों का भला होगा।

हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप मिलेगा रोजगार : श्री चौहान

मुख्यमंत्री नसरूल्लागंज में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए प्रतिमाह हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से बड़ी संख्या में युवक–युवतियों को रोजगार दिलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह भी उनके साथ थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मेले में रोजगार देने आईं कम्पनियों के प्रतिनिधियों तथा रोजगार की तलाश में आए युवक–युवतियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला पुरातत्व पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद सीहोर के कैलेण्डर एवं बुकलेट का विमोचन भी किया।

लकड़ी के खिलौनों की सराहना, ब्राडिंग के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोजगार मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शित लकड़ी के खिलौनों की सराहना की। एक जिला–एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सीहोर जिले का चयन लकड़ी के खिलौनों के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले में बन रहे लकड़ी के खिलौने की ब्राडिंग के निर्देश दिए। रोजगार मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रर्दशनियों का अवलोकन भी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया।

दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व सहायक उपकरण वितरित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोजगार मेले में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल व सहायक उपकरण वितरित किए। दिव्यांग हितग्राही शोभा बाई पति श्री अशोक केवट निवासी रानीपुरा और अशोक पिता श्री रमेश निवासी ग्राम रानीपुरा को ट्राईसाइकिल वितरित की। शिवलाल पिता श्री कुन्जीलाल ग्राम चीच, रानी पति लवेन्द्र ग्राम गोपालपुर, गोराबाई ग्राम झाली, सीताराम ग्राम सीगांव, संगीताबाई पति श्री शिवप्रदसाद नगर परिषद नसरूल्लागंज और कमल सिंह पंवार ग्राम जोगला को श्रवण यंत्र वितरित किए गए।

बाँस की खेती से किसान हो रहे हैं समृद्ध

भोपाल। निमाड़ इलाके की पहचान नीम के पेड़, मिर्च और कपास की प्रचलित फसलों से होती आई हैं, पर इस क्षेत्र को बॉस के माध्यम से नई पहचान दिलाने का बीड़ा खरगोन जिले के ग्राम मेनगाँव के विजय पाटीदार ने न केवल उठाया है, बल्कि वे इसमें कामयाब भी रहे हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में दो साल पहले कटंग बाँस के 4 हजार पौधे लगाकर इसकी पूरी मशक्कत के साथ देखभाल की। इसका परिणाम यह निकला कि इन्होंने सब्जी के खेती में पौधा सहारा देने के लिए काम आने वाले 75 हजार रूपये के बाँस के डंडो का उत्पादन कर लिया है।

विजय पाटीदार को बाँस के पौधे लगाने की प्रेरणा इस बात से मिली कि परम्परागत फसलों में काफी मेहनत के बावजूद कई बार घाटा सहन करना पड़ता था। इसलिए वे लगातार इस खोज में लगे रहते थे कि ऐसी कौन–सी फसल पर काम करें, जहाँ कम मेहनत और कम रिस्क में ज्यादा लाभ मिले। इनकी यह खोज बाँस की फसल पर आकर पूरी हुई।

मध्यप्रदेश राज्य बाँस मिशन बाँस के पौधे लगाने पर तीन साल में प्रति पौधा 120 रूपये का अनुदान देता है। इससे किसान की लागत बेहद कम हो जाती है। इसकी खासियत यह भी है कि इस फसल पर कोई बीमारी या कीड़ा नहीं लगता, जिससे महँगी दवा और रासायनिक खाद के उपयोग से मुक्ति मिल जाती है।

चार साल में 40 लाख रूपये की मिलती है फसल

बाँस लगाने के चौथे साल से प्रति भिर्रा न्यूनतम 10 बाँस तकरीबन 40 फीट लम्बे प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह 40 हजार पौधों से 40 हजार बाँस उपलब्ध हो जाते हैं। प्रति बाँस 100 रूपये के मान से बिक्री होने पर लगभग 40 लाख की फसल मिलेगी। इन बाँसो को खरीददार स्वयं खेत तक आकर ले जाया करते हैं। बाँस की फसल से चौथे साल में प्रति एकड़ एक हजार क्विंटल बाँस की सूखी पत्ती प्राप्त होती है। इस पत्ती को जमीन में गाड़कर उच्च गुणवत्ता की कम्पोस्ट खाद भी बनाई जाती है, जिसका उपयोग सब्जी और अन्य तरह की खेती में भी कर सकते है।

बाँस की कतारों के बीच में मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक और

लहसुन की फसल उगाई जा सकती है। बाँस की कतारों में होने से इन फसलों में पानी कम लगता है और गर्मी में विपरीत प्रभाव से बच जाने की वजह से अच्छा उत्पादन होता है। विजय पाटीदार ने इन प्रयोगों को आजमाया भी है। उन्होंने बताया कि बाँस के पौधो की कतारों में इन्टरक्रापिंग का भी प्रयोग किया है।

बाँस की फसल से किसानों को ''सोने पर सुहागा'' होने जैसी बात है। इस तरह के क्षेत्र में शीतलता प्रदान करने के साथ ही कार्बन डाईऑक्साईड के तीव्रता को सोखकर बड़ी मात्रा में मानव जीवन को ऑक्सीजन भी प्रदान करता है अर्थात जलवायु परिवर्तन की संख्या से निजात दिलाने में बाँस की फसल पूरी तरह कारगर है।

विजय पाटीदार का कहना है कि कटंग बाँस की उम्र 100 से 110 साल होती है। चौथे साल के बाद अच्छा कटंग बाँस प्राप्त होने लगता है तथा कटाई होने के बाद भी प्रति वर्ष बाँस मिलता रहता है। इस तरह इससे होने वाले आर्थिक लाभ से तीन पीढ़ी तक पेंशन का जुगाड़ हो सकता है।

किसानों को दिया संदेश

विजय पाटीदार ने अपने अनुभव साझा कर क्षेत्रीय किसानों को सलाह दी है कि अपने खेत के 10 प्रतिशत हिस्से में बाँस की फसल को जरूर लगाएँ। इससे कम रिस्क में लगातार अधिक मुनाफा मिलेगा।

अब किसान खुद फसलों की जानकारी भू–अभिलेख में दर्ज करा सकेंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राज्य शासन ने किसान हित में बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत अब किसान अपनी भूमि पर उगाई गई फसलों की जानकारी स्वतः राजस्व विभाग के एमपी किसान एप, लोक सेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाईन, नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से भू–अभिलेख में दर्ज करा सकेंगे।

आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार स्वघोषणा के माध्यम से किसान द्वारा दर्ज कराई गई जानकारी का सत्यापन राजस्व अमले द्वारा किया जायेगा। दरअसल फसल गिरदावरी किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को अभिलेखों में दर्ज करने की प्रक्रिया है। इसकी जानकारी के आधार पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार नीतियां एवं योजनायें तैयार करती हैं।

हरित क्रांति से सियान-क्रांति की ओर बढ़ने के साथ कृषि में नवाचार और विकास आवश्यक : मंत्री डॉ. भदौरिया

कृषि आधारित स्टार्ट–अप्स की NAVAAS के तहत हुई शुरूआत

भोपाल। सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया ने कहा कि राज्य सरकार अपने किसानों के समृद्ध भविष्य के लिए स्थायी कृषि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि भारत को अब हरित क्रांति से सियान क्रांति की ओर बढ़ने की जरूरत है, जो भविष्य में होने वाली वृद्धि के लिए कृषि और नवाचारों के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने यह बात मंगलवार को सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सेल्फ हेल्फ तकनीकियों पर केन्द्रित नवास (NAVAAS अर्थात NAVAchar se Samraddhi), नवाचार और अनुसंधान से समृद्धि की शुरुआत के अवसर पर षफिक्की समिट एंड अवार्ड्स फॉर एग्री स्टार्ट–अप्स ' की वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नवास अंतर्गत विकसित तकनीक छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करने वाली स्व–सहायता प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर केंद्रित होगी। NAVAAS के तहत विकसित उपकरण और तकनीक आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, इनपुट लागत को कम करेंगे, उपज के उत्पादक मूल्य में सुधार करेंगे, फसल अवशेषों से मूल्य पैदा करेंगे, मौसम परिवर्तन से होने वाली फसल क्षति को कम करेंगे और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करेंगे। डॉ. भदौरिया ने कहा कि इसके प्रारंभ होने से कृषक समुदाय प्रौद्योगिकी और ज्ञान के उपभोक्ता बनने के बजाय नवप्रवर्तक और शोधकर्ता बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारी संरचना की उपस्थिति ग्रामीण स्तर तक है। प्रदेश में 4523 से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण, खाद–बीज और सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। नवास के माध्यम से पोषित नवाचार, किसान के परिश्रम और गरिमामय बनाते हुए बेहतर उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक होंगे। उन्होंने कृषि आधारित स्टार्टअप्स को नवास में सहभागिता करने पर बधाई दी। साथ ही आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचारों से लैस एग्रीटेक इको सिस्टम में नए और अधिक कुशल व्यावसायिक मॉडल विकसित करने की क्षमता है और अंततः खाद्य प्रणालियों को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और कुशल बनाया जा सकता है। कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने और कृषि संबद्ध क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों को पेश करने की इस पहल की ओर प्रदेश सरकार एमपी इनक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति को बढ़ावा दे रही है।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि राज्य में अनुकूल वातावरण को देखते हुए, हम NAVAAS पहल में भाग लेने और ग्रामीण भारत में बड़े परिवर्तन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सभी स्टार्ट–अप और इनोवेटर्स का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त रूप से काम करने और बड़े पैमाने पर समाधान प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रदेश के किसान, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए आत्म–निर्भर भारत कार्यक्रम के तहत कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ उठा रहे हैं। यह बुनियादी ढाँचा किसानों का समर्थन करेगा और उद्यमियों को भी अवसर देगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 मेगा फूड पार्क, 6 फूड पार्क, 5 एग्री एक्सपोर्ट जोन, 45 औद्योगिक क्षेत्र, 6 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, 226 बड़े पैमाने पर उद्योग, 206 मध्यम स्तर के उद्योगों के साथ खाद्य प्र–संस्करण का मजबूत बुनियादी ढाँचा है।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि फिक्की एग्री स्टार्ट अप समिट एंड अवार्ड्स निश्चित रूप से एक मजबूत कृषि स्टार्ट अप इको सिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने में मदद करेगा। एग्री स्टार्टअप्स और वेंचर पार्टनर, फिक्की टास्क फोर्स के चेयरमेन श्री हेमेंद्र माथुर ने कहा कि मध्य प्रदेश ने जो विकास देखा है, वह अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण है। भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 600 स्टार्ट–अप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम किसानों की आय बढ़ाने में स्टार्ट–अप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिक्की के महासचिव श्री दिलीप चेनॉय ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन और स्टार्ट–अप नीति भारतीय कृषि स्टार्ट–अप को अगले स्तर तक ले जाएगी। उन्होंने राज्यों और स्टार्ट–अप के बीच निरंतर संवाद की सुविधा के लिए राज्य स्तर पर एग्री–टेक स्टार्ट–अप के लिए एक समर्पित सेल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे।

मृगनयनी मध्यप्रदेश शिल्प कला का केन्द्र संरक्षक : केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी

केंद्रीय मंत्री द्वारा नागपुर में मृगनयनी शोरूम का शुभारंभ

भोपाल। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मृगनयनी मध्यप्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की पारंपरिक कला का बेहतर संरक्षण कर रहा है। उन्होंने यह बात नागपुर के सांस्कृतिक केंद्र परिसर में मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के शोरूम के शुभारंभ अवसर पर कही।

मृगनयनी का यह 39वाँ शोरूम है, जो देश के बड़े और मेट्रोपॉलिटन शहरों में खोला गया है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विभिन्न घटक भी देश की हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की गतिविधियों को अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की निफ्ट और डिजाइन संस्थानों के माध्यम से युवा शिल्पियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे इनकी कला को और परिष्कृत किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री राजीव शर्मा ने बताया कि मृगनयनी भारत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हथकरघा–हस्तशिल्प ब्रांड बन गया है। मृगनयनी के माध्यम से प्रदेश के शिल्प को नई पहचान मिली है।

मध्यप्रदेश की माहेश्वरी, चंदेरी की साड़ियाँ, पीतल शिल्प, पत्थर शिल्प, काष्ठ शिल्प, टेराकोटा शिल्प की मांग पूरी देश में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कृत–संकल्पित है।

शुभारंभ कार्यक्रम के उपरांत मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी को स्मृति–चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने राज्य–स्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन

भोपाल। राज्य शासन द्वारा विभिन्न फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने के लिये राज्य–स्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव–सह–कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में 23 समिति सदस्य बनाये गये हैं। इनमें अपर मुख्य सचिव पशु–पालन, प्रमुख सचिव किसान–कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, आयुक्त/संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण, संचालक किसान–कल्याण तथा कृषि विकास, संचालक मत्स्य–पालन, संचालक पशु–पालन, मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) नाबार्ड, प्रबंधक संचालक दुग्ध महासंघ, प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ, संयोजक एस.एल.बी.सी. प्रदेश के समस्त व्यावसायिक बैंक के राज्य–स्तरीय कार्यालय के प्रमुख, चेयरमेन मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक इंदौर, चेयरमेन मध्यांचल ग्रामीण बैंक सागर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) जबलपुर और आई.सी.ए.आर. के राज्य–स्तरीय कार्यालय के प्रतिनिधि सदस्य बनाये गये हैं। मध्यप्रदेश अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक को समिति का सदस्य एवं संयोजक बनाया गया है।

'पोल्ट्री फार्म का पंजीयन पशुपालन विभाग में करवाना आवश्यक'

भोपाल। पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसानों एवं पशुपालकों को पशुपालन विभाग में पंजीयन करवाना आवश्यक है जिससे इसे व्यवस्थित एवं विकसित किया जा सके एवं आवश्यकता होने पर जानकारी के आधार पर तकनिकी सहायता दी जा सके। इस कारण से किसी भी गतिविधि को नियंत्रित करना तथा लाभान्वित करना संभव हो सकेगा। विभाग द्वारा पोल्ट्री उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने तथा विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए वर्तमान में स्थापित तथा नवीन कुक्कुट प्रक्षेत्र हेचरी का पंजीयन प्रारंभ किया गया है, जिससे कुक्कुट प्रक्षेत्र हेचरी की संख्या का सही आंकलन हो सके। भविष्य में लाभकारी नीतियों का निर्धारण अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा। पंजीयन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा साथ ही निर्धारित पंजीयन शुल्क भी जमा करना होगा।

नीति आयोग के छह सूत्री एजेंडा को जमीन पर उतारेगा मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रखे नीति आयोग की बैठक में अपने विचार

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ–व्यवस्था बनाने के लिए मध्यप्रदेश इस साल 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। नीति आयोग के छह सूत्री एजेंडा को समय–सीमा में प्रदेश में व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर में फैले बिगड़े वन क्षेत्र में निजी सहयोग से वन विकसित करने और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पहल की जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनुपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों का तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से मॉनिटाइजेशन करके इससे प्राप्त राशि का उपयोग विकास कार्यों में करना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न नीति आयोग की संचालन परिषद की छठवीं बैठक में मंत्रालय से वर्चुअल भागीदारी कर विचार व्यक्त कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैठक का आरंभ करते हुए कहा कि कोरोना के समय केंद्र और राज्यों ने मिलकर कार्य किया, जिससे विश्व में भारत की अच्छी छवि बनी है। सभी मिलकर कार्य करते हैं, तो अच्छे परिणाम आते हैं। कृषि प्रधान देश होने के बाद भी खाद्य तेल बाहर से आता है, प्रयास हों कि इसका उत्पादन देश में ही हो। अन्य कृषि उत्पाद भी यहीं खप जाएं, इसके लिए राज्य पहल करें। इस संदर्भ में उपलब्ध संभावनाओं को साकार करें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ईज ऑफ डूईंग के साथ ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दें। अनावश्यक कानून समाप्त हों, नागरिकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने पर बल दें।

नीति आयोग की संचालन परिषद सहयोगी संघवाद का आदर्श उदाहरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नीति आयोग की संचालन परिषद केन्द्र के साथ ही राज्यों में परस्पर संवाद का उपयुक्त प्लेटफार्म तथा सहयोगी संघवाद का आदर्श उदाहरण है। इससे केन्द्र तथा राज्य को विचार–विमर्श करने और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित हुई है, जिसका उपयोग पूरी प्रामाणिकता के साथ जारी है।

आपदा को अवसर में बदलने की प्रेरणा से मिली नई ऊर्जा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कठिन काल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। कई विकसित और समृद्ध देश उस सक्षमता और कुशलता से कोरोना का सामना नहीं कर पाये, जितना भारत ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किया। अपने देश के साथ–साथ दुनिया के कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। आपदा को अवसर में बदलने की प्रेरणा से नई ऊर्जा मिली है।

आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के लिए बनाया रोडमेप

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा दिए गए आत्म–निर्भरता के मंत्र के परिपालन में हमने आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में तत्काल कार्य आरंभ किया। नीति आयोग के सहयोग से वेबिनार्स आयोजित कर रोडमैप तैयार किया। इसके चार आधार स्तंभ भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार और अर्थ–व्यवस्था निर्धारित किए गए। इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य समय–सीमा में प्राप्त किए जाएंगे। नीति आयोग द्वारा राज्यों के साथ विचार–विमर्श कर उनकी परस्थितियों और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छह सूत्री एजेंडे का निर्धारण स्वागत योग्य है। मध्यप्रदेश में छह सूत्री एजेंडा को समय–सीमा में पूर्ण किया जाएगा।

केन्द्रीय बजट आत्म–निर्भर भारत का बजट

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्रीय बजट वास्तव में आत्म–निर्भर भारत का बजट है। पहले केन्द्र और राज्य का बजट एक साथ आता था। इससे राज्य सरकारों का बजट काल्पनिक स्वरूप का ही बन पाता था। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार का बजट पहले आने से राज्य सरकारों के लिए व्यवहारिक एवं वास्तविक बजट बनाना संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्यों से आव्हान किया कि वे परस्पर सहमति से ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, जिन्हें संपूर्ण देश में केन्द्रीय वित्तीय प्रावधान और राज्यों के सहयोग से एक साथ प्राप्त करने के लिए एक साथ प्रयास हों। मुख्यमंत्री ने सभी को नल से जल और हर घर को छत जैसे लक्ष्य लेकर राज्यों द्वारा एक साथ कार्य आरंभ करने का सुझाव दिया। इससे कुछ प्राथमिकताएँ पूरा देश एक साथ प्राप्त करने में सफल हो सकेगा।

ग्लोबल मेन्युफेक्चरिंग हब

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत को ग्लोबल मेन्युफेक्चरिंग हब बनाने के लिए मध्यप्रदेश में ''स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज'' व्यवस्था आरंभ की गयी है। इज ऑफ डूईंग बिजनेस की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम हमें करना है। स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर कौशल विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क विकसित किया जा रहा है।

जिलों में हो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों के हुनर और विशेषताओं को देखते हुए ''एक जिला–एक उत्पाद'' पर आरंभ कार्यों के अंतर्गत अमरकंटक क्षेत्र में मिलने वाली वन औषौधियों, नीमच–मंदसौर में लहसुन, बुरहानपुर में केले के उत्पाद के बेहतर व्यापार के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

तीनों कृषि कानून क्रांतिकारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये तीनों कृषि कानून क्रांतिकारी हैं। ये तीनों कानून किसानों की आय दोगुनी करने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जारी है। देश को कृषि के विविधीकरण के बारे में सोचना होगा। मध्यप्रदेश में अनाज के अलावा फूलों, फलों के उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि से कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने का कार्य किया जा रहा है।

खाद्य तेल में आत्म–निर्भरता के लिए प्रयास होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खाद्य तेल में आत्म–निर्भरता की आवश्यकता बताई है। उन्होंने प्रदेश की और से आश्वस्त किया कि जिस प्रकार मध्यप्रदेश में दालों का उत्पादन हुआ, उसी प्रकार खाद्य तेल में आत्म–निर्भरता के लिए भी भरपूर प्रयास किये जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और जीरो बजट की खेती भी देश के लिए जरूरी है। प्रदेश में इस दिशा में हो रहे कार्यों और स्व–सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी देते हुए श्री चौहान ने कहा कि इसे आंदोलन का रूप देना आवश्यक है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में पहल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नयी पहल करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आकांक्षी जिलों के साथ–साथ 50 आकांक्षी विकासखण्डों में भी विकास गतिविधियाँ जारी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के राष्ट्र के विकास के प्रयासों की सराहना की। बैठक में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी विचार व्यक्त किये।

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार योजना

दतिया। उपभोक्ता जागरूकता को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य में प्रतिवर्श विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च के अवसर पर उपभोक्ता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता, व्यक्तियों को राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार प्रदाय किये जाते है। साथ ही निबंध एवं पोस्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदाया किया जाता है। इस हेतु जिले की भ्ालाओं निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।

खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 15 मार्च वि व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर उपक्त प्रतियोगताओं में चयनित आवेदकों को पुरस्कृत किया जायेगा।

प्रदेश का अति सघन वन क्षेत्र 2437 वर्ग किलोमीटर बढ़ने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की सराहना

वन आधारित गतिविधियों एवं वनोपजों के विक्रय में रोजगार बढ़ाने के निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र में 2437 वर्ग किलोमीटर अर्थात 2 लाख 43 हजार 700 हेक्टयर की वृद्धि होने पर वन समितियों और वन विभाग के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिये बड़ी उपलब्धि है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट में यह तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2005 में प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र 4239 वर्ग किलोमीटर था, जो 2019 में बढ़ कर 6676 वर्ग किलोमीटर अर्थात 6 लाख 67 हजार 600 हेक्टयर हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समुदाय की भागीदारी से वनावरण में वृद्धि होने पर वन समितियों के कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि वनावरण बढ़ाने वाली वन समितियों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जायेगा। वन समितियों को सशक्त बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा वे स्वयं वन क्षेत्र विस्तार में बेहतर कार्य करने वाली वन समितियों के द्वारा लगाये गये वनों का अवलोकन करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनावरण में वृद्धि के साथ ही वन आधारित गतिविधियों तथा वनोपजों के संग्रहण और विक्रय में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाये। बैठक में बताया गया कि सात लाख 68 हजार व्यक्तियों को 100 दिवस रोजगार देने का एक्शन प्लान तैयार हो गया है, जो एक अप्रैल 2021 से क्रियान्वित होगा। इसके साथ ही 317 ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की गयी है।

बैठक में वन मंत्री कुंवर विजय शाह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल, वन सचिव श्री अजय यादव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री एम. सेलवेन्द्रन तथा वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

प्रदेश में 32 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। समर्थन मूल्य की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है।

अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ेगी

वीर गति प्राप्त वनकर्मियों के आश्रितों की अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये की जायेगी।

लघु वनोपज प्रजातियों का रोपण बढ़ेगा

लघु वनोपज का संवहनीय प्रबंधन के अंतर्गत विभागीय वृक्षारोपण में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जायेगा।

बफर में सफर शुरू

बफर में सफर के अंतर्गत बफर जोन में दिन एवं रात्रि सफारी, हॉट एयर बैलून तथा मचान गतिविधियों को शुरू किया गया है।

बाघ परियोजना

संजय एवं सतपुड़ा बाघ परियोजनाओं के विकसित रहवास में बाघों का पुनर्स्थापन किया जायेगा। इसी तरह गांधी सागर और नौरादेही में बाघ पुनर्स्थापना के लिए गांधी सागर में 56 चीतल और नौरादेही में 318 चीतल पुनर्स्थापित किये गये हैं।

तेंदुआ प्रदेश

बाघ प्रदेश के बाद देश के 26 प्रतिशत तेन्दुओं की संख्या के साथ मध्यप्रदेश तेन्दुआ प्रदेश भी बन गया है। भारत में तेन्दुओं की संख्या 12 हजार 852 है, जबकि मध्यप्रदेश में तेन्दुओं की संख्या 3 हजार 721 है।

बैठक में बताया गया कि 86 वन–धन केन्द्रों के माध्यम से लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन एवं विपणन से 25 हजार हितग्राहियों को वर्ष भर रोजगार देने का लक्ष्य है। बाँस की गुणवत्ता मूल्य संवर्द्धन के लिये 20 बाँस क्लस्टरों का व्यवस्थित विकास किया जायेगा।

इको पर्यटन

इको पर्यटन के लिये 129 स्थल चयनित किये गये है। ईको पर्यटन गतिविधियों के संचालन में वन समितियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अभी तक 350 व्यक्तियों को ईको पर्यटन में रोजगार मिला है। दीर्घ–कालीन लक्ष्य 1300 व्यक्तियों को रोजगार देने का है।

किसान भाई टमाटर, प्याज, बैंगन, मिर्च तथा गोभी की तैयार पौध को मुख्य खेतों में रोपाई करें

टीकमगढ़। आनेवाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने तथा आसमान साफ रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 32–33 डि.से. के आस–पास तथा रात का न्यूनतम तापमान 10–12 डि.से. के आस–पास रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 08 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना हैं। आनेवाले 5 दिनों के दौरान तापमान में वृद्धि तथा आसमान साफ रहने की संभावना को देखते हुए, किसान भाई फसलों (विशेषकर गेंहू) तथा सब्जियों में सिंचाई का कार्य करें तथा साथ ही कीट–ब्याधियों की निगरानी का कार्य सुचारू रूप से करते रहें। गेहूँ की फसल में तना बेधक कीट का प्रकोप हो रहा है अतरू किसान भाई निरीक्षण करते रहें। इसके नियत्रण हेतु ट्राइजोफास40 ई.सी. दवा की 2 मिली लीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मटर तथा सरसों की फसल में पाउडरी मिल्डयू (भभूतिया रोग) रोग का किसान भाई फसल का निरीक्षण करें, पाये जाने पर बचाव हेतु सल्फर पाउडर दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में मांहू का प्रकोप बढ़ सकता है। अतरू किसान भाई फसल का निरीक्षण करें तथा बचाव हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा 1.0 मिली. मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चना तथा मटर की फसल में तम्बांकू तथा चने की इल्ली की सक्रीयता देखी जा रही है। अतरू किसान भाई फसल का निरीक्षण करें। मिर्च, टमाटर, तथा बैंगन की फसल में पत्ती सिकुड़न (लीफ कर्ल) रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, इससे बचाव हेतु किसान भाई, मिथायल डेमेटॉन 25 ई.सी. दवा की 2 मिली लीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाई भिंड़ी की उन्नत प्रजाति की बुआई करें तथा बुआई से पूर्व बीज को रातभर (12 से 14 घंटे तक) बाविस्टन के घोल में (2 मिली. प्रति लीटर पानी के घोल) भिगोकर रखें। नीबू में सिंचाई करना बन्द करें ताकि इसमें पर्याप्त मात्रा में फूल आ सकें। आम के पौधें में फूल आने का समय है, किसान भाई फसल का निरीक्षण करें तथा फूल का रस चुसने वाले कीड़ो का प्रकोप पाये जाने पर बचाव हेतु डाईक्लोरोवास 76 प्रतिशत दवा की 2.0 मि.ली. 1 लीटर पानी में धोल बनाकर एक छिड़काव करें। किसान भाई, दुधारु पशुओं के आहार में संतुलित पशु आहार का समावेश करे, ताकि बदलते मौसम में दुग्ध उत्पादन प्रभावित न हो। आनेवाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने तथा आसमान साफ रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, भेड़ पालकों को सलाह दी जाती हैं कि वे ऊन कतरन का कार्य प्रारम्भ करें।

खाद्यान्न उत्पादन के साथ प्रदेश में वेयर हाउस की भी मांग बढ़ी रू मंत्री श्री डंग

भोपाल। मध्यप्रदेश खाद्यान्न, दलहन, तिलहन आदि उत्पादन में बहुत तेजी से देश में अग्रणी स्थान बना रहा है। ऐसे में वेयर हाउस की मांग भी कई गुना बढ़ गई है। अधिक से अधिक वेयर हाउस बनवा कर हम न केवल खाद्य समाग्री का सुरक्षित भंडारण कर सकेंगे बल्कि किसान को भी समय–समय पर उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने आज मंदसौर जिले के ग्राम खेताखेड़ा में वेयर हाउस का भूमि–पूजन करते हुए यह बात कही।

कोल्ड-स्टोरेज के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लें

विभागीय समीक्षा बैठक में उद्यानिकी, खाद्य प्र–संस्करण राज्य मंत्री श्री कुशवाह

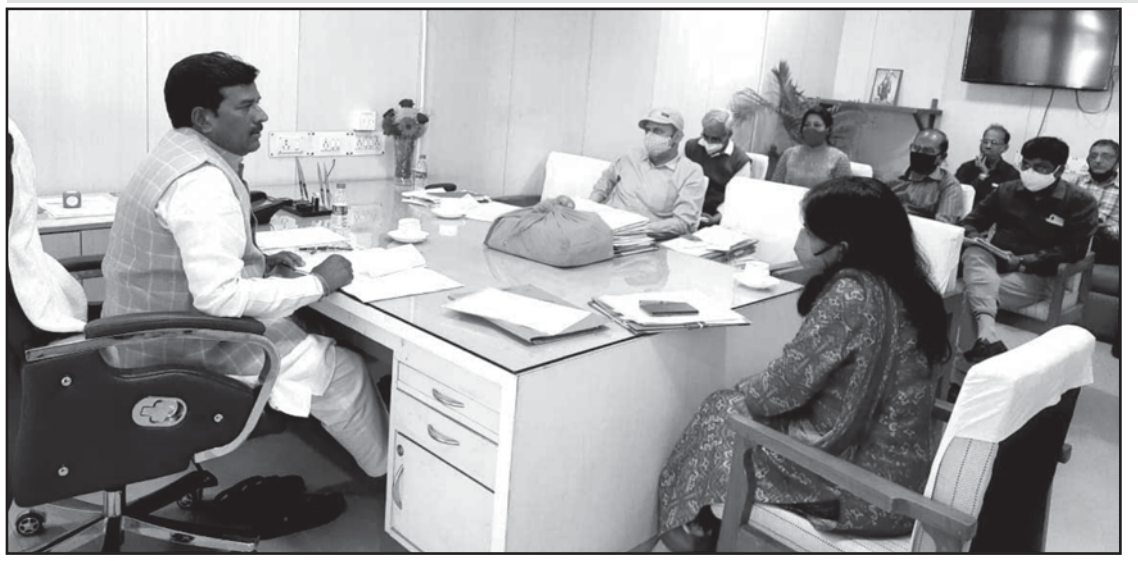

भोपाल। उद्यानिकी फसलों से जुड़े किसानों को उनके उत्पाद रखने के लिये कोल्ड–स्टोरेज के विभाग को प्राप्त प्रस्ताव पर शीघ्रता से स्वीकृति दी जाये। उद्यानिकी, खाद्य प्र–संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह बात कही।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कोल्ड–स्टोरेज के लिये विभाग को प्राप्त प्रस्ताव की वर्गवार समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि विभाग को 500 मीट्रिक टन क्षमता के 707, एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के 463 और 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के 71 कुल 1241 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि प्रस्ताव पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जाये और शीघ्र स्वीकृति दी जाये। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में विभाग द्वारा 60 करोड़ के कोल्ड–स्टोरेज के निर्माण करवाये जाने हैं। कोल्ड–स्टोरेज के निर्माण पर 35 प्रतिशत शासकीय अनुदान है।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि विभागीय अधिकारियों की कमी के चलते मॉडल विकासखण्डों और नर्सरियों में पर्यवेक्षण के लिये अन्य विभागों से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाये। श्री कुशवाह ने मॉडल विकासखण्डों में दिये गये लक्ष्य के अनुसार किये गये कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में संभागीय स्तर पर महिला, कृषक प्रशिक्षण शिविर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की प्रदर्शनियों को आयोजित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। विभाग की 262 फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को उन्नयन करने की योजना की अद्यतन प्रगति के संबंध में भी चर्चा की गई।

बैठक में उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों और विकासखण्डों को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में बनाने के संबंध में भी चर्चा हुई। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि राज्य की उद्यानिकी विभाग की गतिविधियों एवं योजनाओं में देश में पहले स्थानों में गिनती हो। विभाग को इस तरह लक्ष्य तय करके कार्य करना है। बैठक में प्रमुख सचिव, उद्यानिकी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

8290 हेक्टेयर क्षेत्र में लघु वनोपज की योजना मंजूर : वन मंत्री कुंवर शाह

भोपाल। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि लघु वनोपज संघ द्वारा 8 हजार 290 हेक्टेयर क्षेत्र में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण की योजना मंजूर की गई है। विभागीय वृक्षारोपण में लघु वनोपन प्रजातियों के रोपण का दायरा 5 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है।

वन मंत्री ने बताया कि विभागीय पौधा रोपण में स्थानीय प्रजातियों के साथ लघु वनोपज से जुड़ी वृक्ष प्रजातियों को प्राथमिकता से लगवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर भागीदारी से बिगड़े वनों का सुधार कार्यक्रम में आगामी 3 वर्ष में 5 हजार ग्राम वन समितियों को लाभान्वित कराया जाएगा। इससे वनों का संरक्षण और ग्रामीणों की आजीविका को सुदृढ़ किया जा सकेगा। वनों के सुधार और जंगलों के बचाव के लिए 317 ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कर विदोहन प्रारंभ कर दिया गया है।

साढ़े सात लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

वन मंत्री कुंवर शाह ने बताया कि वन प्रबंधन के तहत वर्ष 2021–22 में 7 लाख 68 हजार लोगों को 100 दिवस का रोजगार दिया जायेगा। इसके लिए यथाशीघ्र मास्टर प्लान तैयार कराया जाएगा।

अधिकारी वनांचल में करें रात्रि विश्राम

वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने वन विभाग के अधिकारियों को वनांचल क्षेत्रों का सघन दौरा के साथ ही रात्रि विश्राम कर ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने के निर्देश भी दिए हैं।

रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण के लिए आवेदन ऑनलाईन करें'

भोपाल। सहायक श्रमायुक्त, भोपाल श्रीमती जेसमिन सितारा ने बताया है कि म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क म.प्र.राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2019 के माध्यम से जिन स्थापनाओं में एक से तीन कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण शुल्क दौ सौ रूपये एवं जिन स्थापनाओं में तीन से अधिक कर्मचारी हैं उन स्थापनाओंध्रजिस्ट्रीकरण शुल्क 250 रूपये निर्धारित किया गया है । रजिस्ट्रीकरण – नवीनीकरण के लिए आवेदन श्रमायुक्त विभाग के पोर्टल www-labour-mp-gov-in पर ऑनलाईन किया जा सकता है। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जिन स्थापना संचालकों द्वारा 15 फरवरी 2014 के पश्चात स्थापना का रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण प्राप्त किया गया है, उन स्थापनाओं का नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

"आईआरएडी" एप से दुर्घटनाओं का सटीक डाटा मिलेगा

खण्डवा। राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समेकित सड़क दुर्घटना डाटा बेस "आईआरएडी" एप तैयार किया गया है। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में मध्यप्रदेश सहित 6 राज्यों को शामिल किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री डी.सी. सागर ने बताया कि आईआरएडी एप के माध्यम से दुर्घटनाओं का सटीक डाटा मिल सकेगा।

एडीजी श्री सागर ने बताया कि आईआरएडी एप से सड़क दुर्घटना से संबंधित समेकित जानकारी संग्रहित की जा सकेगी। इस जानकारी से प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर सड़क दुर्घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार के विश्लेषण किये जा सकेंगे। एप द्वारा घटना स्थल के फोटो और वीडियो तैयार किये जा सकेंगे, जिससे दुर्घटनाओं का सटीक रिकार्ड निर्मित एवं संधारित होगा। उन्होने बताया कि इस एप में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में पुलिस, परिवहन, राजमार्ग, स्वास्थ्य और 108 एम्बुलेंस से संबंधित कार्य क्षेत्र तथा संबंधित एजेंसियों के कर्त्तव्यों की जानकारी है। इसका उपयोग कर पुलिस एवं अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी एजेंसियाँ दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना संबंधी डाटा एकत्रित कर एप में प्रविष्ट करेंगी। संकलित समेकित डाटा का उपयोग कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी

घोषणा फार्म चार (नियम 8)

1.	प्रकाशन स्थल	:	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं:		हां
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो।	:	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।

मैं दिनेशचन्द्र शर्मा एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

दिनांक 16 फरवरी 2021

(दिनेशचन्द्र शर्मा)
प्रकाशक के हस्ताक्षर

विकास और मजबूत कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता : श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान का राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन ने किया अभिनंदन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आम जनता के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए सभी नागरिकों विशेष रूप से माताओं–बहनों के सम्मान पर आँच नहीं आने दी जाएगी। विकास और मजबूत कानून–व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिले, इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू हो, बात पढ़ाई–लिखाई की हो या रोजगार, खाद्यान्न वितरण या उपचार की, कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कहीं किसी भेदभाव को स्थान नहीं दिया जाएगा। सभी वर्गों के मध्य सद्भाव आवश्यक है। यही भाईचारा हमारी ताकत भी है। भारत भूमि ने सदैव इस भावना को बल भी दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन द्वारा वरिष्ठ नेता स्व. आरिफ बेग की 86वीं जयंती पर रवीन्द्र भवन, भोपाल में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का प्रदेश के व्यवस्थित, तीव्र विकास और सुदृढ़ कानून व्यवस्था लागू करने के लिए अभिनंदन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व. आरिफ बेग का स्मरण करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किये। उन्होंने कहा कि स्व. आरिफ बेग चलती–फिरती पाठशाला थे। उन्होंने स्वयं स्व. श्री बेग से भाषण कला सीखी। स्व. बेग एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था थे। वे दिलों पर राज करते थे। विधायक, सांसद और केन्द्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अमूल्य सेवाएँ दीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आपातकाल की अवधि में स्व. श्री बेग के साथ कारावास में बिताए वक्त को भी याद किया, जब अनेक बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कारावास में स्व. श्री बेग सभी का हौसला बढ़ाते थे। उनका संदेश यही होता था कि जुल्म के आगे झुकना नहीं है। उनकी शख्सियत स्व. ठाकरे जी, राजमाता जी और अटल जी के समकक्ष थी। कौमी एकता के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया। वे काफी विनम्र थे और खेलों में भी उनकी रूचि थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व. श्री आरिफ बेग के सेवा कार्यों को उनके सुपुत्र श्री नुरूल हसन बेग द्वारा आगे बढ़ाने की पहल प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन द्वारा मुस्लिम समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने के प्रयास की भी सराहना की। इस अवसर पर श्रीमती शाइस्ता बेग, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री रफत वारसी, फाउंडेशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न प्रकाशनों और डाक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन भी किया।

किसानों को उन्नत कृषि तकनीक अपनाने करें प्रोत्साहित : मंत्री श्री पटेल

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का किया भ्रमण

भोपाल। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये जरूरी है कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से निरंतर अवगत कराया जाये। उन्हें उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की कृषि इकाइयों के भ्रमण के दौरान जबलपुर में यह बात कही। उन्होंने प्रदेश की दूसरी कृषि ओपीडी का शुभारंभ किया। श्री पटेल ने कृषि महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया।

मंत्री श्री पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा चना, अलसी और विसिया (चारा) की तीन नई प्रजातियों के राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ''एक जिला–एक उत्पाद'' के तहत प्रत्येक विकासखण्ड में उन्नत फसलों की किस्मों का उत्पादन होना चाहिये। किसानों को उन्नत तकनीकों से अवगत कराना चाहिये। तकनीकों को अपनाने के लिये जागरूक करना चाहिये, जिससे कि किसान कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से भी मंत्री श्री पटेल ने सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कृषकों के अथक परिश्रम और सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से कृषि उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। नये कृषि कानूनों से किसानों को नई सुविधाएँ मिलेंगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से लाभान्वित होकर किसान वेयर–हाउसिंग, ग्रेडिंग, कोल्ड–स्टोरिंग और प्रोसेसिंग इत्यादि की यूनिट भी लगा सकेंगे।

प्रदेश की दूसरी कृषि ओपीडी जबलपुर में

कृषि मंत्री श्री पटेल ने सोमवार को जबलपुर में प्रदेश की दूसरी कृषि ओपीडी का शुभारंभ किया। उन्होंने निर्देशित किया कि कृषि ओपीडी को प्रभावी रूप से संचालित किया जाये, ताकि किसानों की फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। इसका व्यापक तौर पर प्रचार–प्रसार किया जाना भी सुनिश्चित करें। श्री पटेल ने कहा कि इससे लाभान्वित होकर किसान फसल संबंधी बीमारियों का समय रहते बेहतर उपचार कर सकेंगे।

स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के मार्केटिंग की बेहतर व्यवस्था होगी

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के लिये स्व–सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के मार्केटिंग की और बेहतर व्यवस्था की जाना होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व–सहायता समूहों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य मंत्री श्री पटेल भोपाल हाट में सरस मेले के अवलोकन के बाद स्व–सहायता समूह के सदस्यों से बात कर रहे थे। श्री पटेल ने मेले में प्रदर्शित उत्पादों को देखा और स्व–सहायता समूह की गतिविधियों को समझा।

राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ''एक जिला–एक उत्पाद'' को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संस्कृति अत्यंत समृद्ध रही है। यहाँ की कारीगरी की देशभर में ख्याति है। उन्होंने स्व–सहायता समूह के सदस्यों से अपने उत्पादों को अधिक से अधिक मेलों में पहुँचाने की बात कही। राज्य मंत्री श्री पटेल ने महिला स्व–सहायता समूह की सदस्यों से उनकी दिनचर्या के बारे में जाना।

17 राज्य शामिल हो रहे हैं सरस मेले में

भोपाल हाट में सरस मेला 22 फरवरी तक चलेगा। मेले में 17 राज्यों के पारम्परिक ड्रेस मटेरियल, डेकोरेटिव आयटम, ज्वेलरी, टेराकोटा, क्रॉकरी आयटम प्रमुख रूप से प्रदर्शित किये गये हैं। ज्वेलरी में भील–गोड़ और राजस्थानी ऑर्ट विशेष रूप से पसंद की जा रही है। इसके साथ ही पारम्परिक पेंटिंग्स को भी प्रदर्शित किया गया है। सरस मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। सरस मेले का आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से किया जा रहा है।

पथ विक्रेता सम्मान से करें अपने काम-धंधे : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से किया संवाद

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेरा हर संभव प्रयास है कि प्रदेश के बेटा–बेटी, भाई–बहन अपने स्वयं के काम–धंधे संचालित करें और सम्मान से जीवन जिएं। यह हो गया तो मानूँगा कि मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मिंटो हाल में 40 हजार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को एक साथ दस–दस हजार रुपये के ऋण उपलब्ध कराने के लिए पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह और अपर मुख्य सचिव ग्रामीण एवं पंचायत विकास श्री मनोज श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शहरी पथ व्रिकेताओं के लिए योजना आरंभ की गई थी। इससे प्रेरणा लेकर कोरोना काल में प्रभावित हुए छोटे कारोबारियों की मदद के लिए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के लिए भी योजना आरंभ की गई है। छोटे स्तर पर संचालित काम– धंधों के लिए पूँजी के साथ–साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे पथ विक्रेता अपने कार्य को अधिक कुशलता से संचालित कर सकेंगे, उसमें लगातार विस्तार भी होगा। अब–तक प्रदेश में 1 लाख 41 हजार से अधिक हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

कोरोना से सतर्क रहें : मुख्यमंत्री श्री चौहान

आरंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से कोरोना से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों जैसे मास्क लगाना, दो गज की दूरी, बार–बार हाथ धोना और सेनेटाईजर का उपयोग जरूरी है। इसमें लापरवाही न बरती जाए। केरल और महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आवश्यक सावधानियाँ अपनाकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना चला गया है, यह मानकर लापरवाह होने का समय नहीं है।

ग्राम स्तर पर लोगों को सशक्त करना मेरी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँव–कस्बों में छोटी पूँजी से संचालित हो सकने वाले कार्यों में उद्योगपति अपनी घुसपैठ न बना पाएं। इसके लिए ही ग्रामीण पथ विक्रेताओं को सरलता से ऋण उपलब्ध कराने और सूदखोरों के चंगुल से मुक्त रखने के लिए यह योजना संचालित की गई है। ग्राम स्तर पर लोग सशक्त हों, इस उद्देश्य से ही शाला यूनिफार्म की सिलाई का कार्य और पोषण आहार का कार्य स्व–सहायता समूहों को सौंपा गया है।

मेहनत की इज्जत सुनिश्चित होगी–पथ विक्रेताओं को मिलेंगे पहचान–पत्र

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पथ विक्रेताओं को पहचान–पत्र जारी किए जाएंगे। उनके काम के स्थान के निर्धारण के साथ–साथ पंजीयन प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इस दिशा में और क्या नवाचार हो सकता है, इस संबंध में भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

जिंदगी आसान बनाना है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोटी–कपड़ा और मकान, पढ़ाई–लिखाई और बीमारी में दवाई का इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के लोगों की जिन्दगी को आसान बनाना है। इस दिशा में अगले तीन साल में गाँवों के सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराने की योजना है। ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया।

बहनें ठीक तो मामा खुश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने देवास के रालामंडल की श्रीमती पिंकी से पूछा कि योजना की जानकारी कैसे मिली और पैसे मिलने में कोई परेशानी तो नहीं आई। श्रीमती पिंकी ने बताया कि योजना में मिले ऋण से सिलाई का काम बढ़ा है और अब स्वयं की दुकान खोलने और इंटरलॉक की मशीन लेने की योजना है। श्रीमती पिंकी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से उनका हाल पूछा तो श्री चौहान ने कहा कि– ''बहनें ठीक तो मामा खुश''

रामा टी–स्टॉल पर पिएंगे चाय

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री रैकवार की कहानी से प्रदेश के बहुत से लोगों को मदद मिलेगी। दमोह के ग्राम बांदकपुर में रामा टी–स्टॉल चाय की दुकान चला रहे श्री रामचरण रैकवार से मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उसकी दुकान पर चाय पीने जरूर आएंगे। श्री रैकवार ने ऋण लेने और उससे अपने काम को बढ़ाने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी।

कोरोना काल में पूरी तरह बन्द हो गई थी किराना दुकान

विदिशा जिले के ग्राम इमलिया के श्री वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि– कोरोना काल में किराना दुकान पूरी तरह बन्द हो गई थी। इस योजना में मिले ऋण से उन्होंने सब्जी और फल की दुकान शुरू की। दुकान से अब प्रतिदिन लगभग पाँच सौ रुपये की आय हो जाती है। वे अब हर रोज किराने का एक आयटम अपनी दुकान में शामिल करते जा रहे हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रायसेन जिले के श्री नमन कुशवाह, श्री सत्येन्द्र सोनी, श्रीमती मुन्नी बाई, सीहोर जिले की श्रीमती सीमा बाई, श्री ज्ञान सिंह और श्री देवराज सिंह को ऋण राशि के चेक प्रदान किये।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत राज्य शासन की क्रेडिट गारंटी पर पथ विक्रेताओं को रोजगार की बेहतरी के लिए बैंकों से दस–दस हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें ऋण का ब्याज अनुदान भी राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से छोटे कारोबारियों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उनके व्यवसाय पुनः प्रारंभ कराने के लिए आसान कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा यह योजना आरंभ की गई। योजना में अभी तक 14 लाख 15 हजार से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन कामगार सेतु पोर्टल से कराया जा चुका है।

मनरेगा का वार्षिक लक्ष्य बढ़ कर हुआ 33 करोड़ मानव दिवस

भोपाल। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मनरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश का वार्षिक लेबर बजट रिवाइज कर 33 करोड़ मानव दिवस का किया है। मनरेगा अंतर्गत अब प्रदेश में 33 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य हो गया है, जिसे 31 मार्च 2021 तक पूरा करना होगा।

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में कोराना काल में मनरेगा श्रमिकों को हर हाथ को काम मुहैया कराकर इस लक्ष्य को माह सितम्बर 2020 में प्राप्त कर लिया था। जिसे भारत सरकार ने पुनरीक्षित कर 28 करोड़ 50 लाख मानव दिवस कर दिया था। प्रदेश द्वारा 28 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के लक्ष्य को 25 जनवरी 2021 तक हासिल कर लिया। भारत सरकार द्वारा पुनर्लक्षित करते हुए 31 करोड़ मानव दिवस का कर दिया था। मध्यप्रदेश में 18 फरवरी की स्थिति में 30 करोड़ 63 लाख मानव दिवस सृजित हो चुके है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ गुरूवार को आयोजित हुयी वीडियो कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश में मनरेगा के पूर्व लक्ष्य 31 करोड़ मानव दिवस को को संशोधित करते हुए 33 करोड़ मानव दिवस कर दिया है। दो करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य बढ़ जाने से प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को जहाँ रोजगार के अतिरिक्त अवसर मुहैया होंगे वहीं मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को 380 करोड़ रूपये मजदूरी के रूप में अतिरिक्त प्राप्त होंगे।

प्रदेश में मनरेगा अन्तर्गत ग्रामीण जॉब–कार्डधारी परिवारों को हर हाथ को काम मुहैया कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 अंतर्गत 52 लाख 47 हजार परिवारों के 98 लाख 79 हजार श्रमिकों को 30 करोड़ 63 लाख मानव दिवस का रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। कोविड काल में मनरेगा अंतर्गत सृजित मानव दिवस योजना प्रारंभ से अब–तक के वर्षों में रिकार्ड सर्वाधिक है। मनरेगा के तहत कोविड काल, वर्ष 2020–21 में 6 लाख 45 हजार हितग्राही मूलक और सामुदायिक कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में 6 लाख 74 हजार कार्य प्रगतिरत हैं।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।